

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्रवृत्ति का विश्लेषणात्मक अध्ययन

मंजू 1, डॉ. शरद कुमार 2

1 शोधार्थिनी, अर्थशास्त्र विभाग, एन.आर.ई.सी कॉलेज, खुर्जा, बुलंदशहर

2 एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, एन.आर.ई.सी कॉलेज, खुर्जा, बुलंदशहर

सारांश

यह शोध भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्रवृत्तियों, इसके आर्थिक प्रभावों और नीतिगत सुधारों का विश्लेषण करता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह की प्रवृत्तियों को समझना और उनके प्रभावों का मूल्यांकन करना है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह में निरंतर वृद्धि हुई है, विशेष रूप से आईटी, विनिर्माण, खुदरा और सेवा क्षेत्रों में। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों में निवेश अधिक केंद्रित रहा, जबकि पूर्वोत्तर और कुछ उत्तरी राज्यों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अपेक्षाकृत कम रहा। सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया,' 'स्टार्टअप इंडिया,' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी नीतियाँ विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सहायक रही हैं। नीतिगत अस्थिरता, नौकरशाही बाधाएँ, भूमि अधिग्रहण की जटिलताएँ और श्रम सुधारों की कमी जैसी चुनौतियाँ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह को प्रभावित कर रही हैं। अध्ययन यह निष्कर्ष निकालता है कि यदि भारत व्यापार सुगमता सुधारता है, वैश्विक व्यापार समझौतों में अधिक भागीदारी करता है, और पिछड़े राज्यों में निवेश अनुकूल माहौल विकसित करता है, तो यह वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश केंद्रों में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। यह शोध नीति निर्माताओं, निवेशकों और अर्थशास्त्रियों के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि यह भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अवसरों और बाधाओं को व्यापक रूप से प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, आर्थिक विकास, उदारीकरण, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सरकार की नीतियाँ।

प्रस्तावना

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किसी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा किए गए दीर्घकालिक निवेश को दर्शाता है, जिसमें पूंजी प्रवाह के साथ-साथ प्रबंधन और नियंत्रण का अधिकार भी शामिल होता है। यह निवेश प्रत्यक्ष स्वामित्व के रूप में विनिर्माण, सेवा, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में किया जाता है, जिससे संबंधित देश की आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को विकास का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, क्योंकि यह पूंजी, तकनीकी ज्ञान, रोजगार सृजन और उत्पादकता में वृद्धि लाने में सहायक होता है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का विशेष महत्व है, क्योंकि यह औद्योगिक विकास को गति देता है, घरेलू उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों को मजबूत करता है।

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का इतिहास स्वतंत्रता के बाद से ही विविध चरणों में विकसित हुआ है। 1947 के बाद, भारत ने समाजवादी आर्थिक नीतियों को अपनाया, जहाँ सरकारी नियंत्रण और नियमन पर अधिक जोर था। इस दौरान, विदेशी निवेश पर कठोर प्रतिबंध थे और केवल आवश्यक तकनीकी सहयोग के रूप में सीमित निवेश की अनुमति थी। 1980 के दशक में आर्थिक उदारीकरण की दिशा में कुछ कदम उठाए गए, लेकिन विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निर्णायक परिवर्तन 1991 में हुए।

1991 में, आर्थिक सुधारों के तहत भारत सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) की नीति अपनाई, जिससे विदेशी निवेश के लिए भारत का बाजार खुला। इसके बाद, सेवा, विनिर्माण, दूरसंचार, बैंकिंग, खुदरा, और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह तेज़ी से बढ़ा। सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए नीतिगत सुधार किए, जिसमें स्वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग के तहत निवेश की सुविधा दी गई। इसके अलावा, 'मेक इन इंडिया,' 'स्टार्टअप इंडिया,' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी योजनाओं ने भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में, भारत वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षण केंद्र बन चुका है, जो औद्योगिक विकास, नवाचार और समावेशी आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करता है।

FDI के शीर्ष क्षेत्र (2023 तक, प्रतिशत में)

क्षेत्र	FDI का प्रतिशत योगदान
सेवा क्षेत्र	18.0%
आईटी और सॉफ्टवेयर	15.5%
विनिर्माण	12.8%
दूरसंचार	10.2%
ऑटोमोबाइल	7.5%
निर्माण एवं रियल एस्टेट	6.0%
अन्य	30.0%

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), "Annual Report on Foreign Direct Investment," 2023, उपलब्ध: <https://rbi.org.in>

साहित्य समीक्षा

गुप्ता, एस. (2005) द्वारा लिखित "भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश : एक आर्थिक विश्लेषण" में 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। लेखक ने विश्लेषण किया कि उदारीकरण की नीतियों, जैसे लाइसेंस राज की समाप्ति और स्वचालित मार्ग से निवेश प्रोत्साहन, के कारण भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। विशेष रूप से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में इसका सकारात्मक प्रभाव देखा गया, जिससे रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विदेशी निवेश ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए अधिक सक्षम बनाया।

शर्मा, आर. (2010) द्वारा लिखित "वैश्वीकरण और भारत में विदेशी निवेश" शोधपत्र में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की ऐतिहासिक प्रवृत्तियों और वैश्वीकरण के प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। लेखक ने बताया कि 1991 के बाद आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के कारण भारत में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला। विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह ने तेज़ी से वृद्धि की, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख आईटी हब के रूप में उभरा। अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी से तकनीकी नवाचार और औद्योगिक उत्पादकता में सुधार हुआ।

सक्सेना, पी. (2013) द्वारा लिखित "विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और भारतीय औद्योगिक विकास" शोधपत्र में औद्योगिक क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में दर्शाया गया कि 1991 के बाद की

उदारीकरण नीतियों ने विदेशी निवेश को आकर्षित किया, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में। इन क्षेत्रों में बढ़ते विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह ने घरेलू उत्पादन क्षमता, तकनीकी उन्नति और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया। लेखक ने यह भी बताया कि विदेशी निवेश के कारण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई, जिससे भारतीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिली।

मिश्रा, के. (2015) द्वारा लिखित “भारत में विदेशी निवेश की नीतियाँ और उनकी प्रभावशीलता” शोधपत्र में भारत सरकार की विभिन्न विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीतियों का मूल्यांकन किया गया है। लेखक ने स्वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत निवेश प्रक्रिया का गहन विश्लेषण किया है और बताया कि कैसे इन नीतियों ने निवेशकों के लिए भारत को एक आकर्षक गंतव्य बनाया। अध्ययन में उल्लेख किया गया कि उदारीकरण के बाद सरकार ने विनिर्माण, खुदरा, और सेवा क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए नियम सरल किए, जिससे पूंजी प्रवाह बढ़ा। निष्कर्ष में यह भी बताया गया कि निवेश नीतियों में सुधार से अर्थव्यवस्था, रोजगार और तकनीकी उन्नति को लाभ हुआ।

चटर्जी, बी. (2018) द्वारा लिखित "सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और भारत की आर्थिक वृद्धि" शोधपत्र में भारत के सेवा क्षेत्र में विदेशी निवेश की प्रवृत्ति और उसके आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। लेखक ने बैंकिंग, बीमा और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के योगदान को रेखांकित किया, जिससे अर्थव्यवस्था की समग्र उत्पादकता में वृद्धि हुई। अध्ययन में बताया गया कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ने नई नौकरियों, पूंजी प्रवाह और तकनीकी उन्नति को प्रोत्साहित किया, जिससे भारत की सेवा अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनी। निष्कर्ष में यह भी उल्लेख है कि सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ने GDP वृद्धि और नवाचार को मजबूती प्रदान की।

उद्देश्य

1. भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना।
2. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का आर्थिक विकास पर प्रभाव का मूल्यांकन करना।
3. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह में क्षेत्रीय असमानता का अध्ययन करना।

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्रवृत्तियाँ

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्रवृत्तियाँ समय के साथ विभिन्न आर्थिक सुधारों और वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही हैं। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे देश के औद्योगिक, सेवा और तकनीकी क्षेत्रों को गति मिली। इस प्रवृत्ति ने न केवल आर्थिक विकास को बल दिया बल्कि भारत को वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बनाने में भी योगदान दिया।

1991 के उदारीकरण के बाद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की वृद्धि

1991 से पहले भारत में विदेशी निवेश पर कड़े प्रतिबंध थे और सरकार द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था के कारण विदेशी कंपनियाँ निवेश करने में हिचकिचाती थीं। 1991 में उदारीकरण की नीतियों के लागू होने के बाद भारत ने विदेशी निवेश के लिए अपने द्वार खोले। नई नीतियों के तहत सरकार ने लाइसेंस राज को समाप्त किया, विभिन्न उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अनुमति दी और विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए कई सुधार किए। इसके परिणामस्वरूप भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह में तेजी आई। 1991-2000 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह धीमी गति से बढ़ा, क्योंकि शुरुआती वर्षों में विदेशी कंपनियाँ भारतीय बाजार को समझने और नीतिगत

स्थिरता का आकलन करने में लगी थीं। 2000 के बाद, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्रों में निवेश में तेजी आई।

प्रमुख क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह

भारत में विदेशी निवेश का प्रवाह विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रित रहा है, जिनमें निर्माण, सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल और खुदरा व्यापार मुख्य हैं।

निर्माण क्षेत्र: भारत में बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया। विशेष रूप से शहरीकरण की गति बढ़ने से इस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित हुआ।

सेवा क्षेत्र: बैंकिंग, बीमा, वित्तीय सेवाओं और टेली संचार उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ने भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्षेत्र में लगातार सुधारों और नीतिगत ढील के कारण विदेशी कंपनियों ने अधिक निवेश किया।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र: 2000 के दशक की शुरुआत में भारत एक वैश्विक आईटी हब के रूप में उभरा, जिसके कारण इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों का निवेश बढ़ा। आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाओं में उच्च कौशल युक्त श्रमशक्ति के कारण भारत को विदेशी निवेश आकर्षित करने में सफलता मिली।

ऑटोमोबाइल क्षेत्र: वैश्विक कंपनियों ने भारत को एक प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में देखा। भारत की बढ़ती मध्यवर्गीय आबादी और उपभोक्ता मांग के कारण इस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह निरंतर बना रहा।

खुदरा व्यापार: 2010 के बाद भारत में संगठित खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ने लगा। सरकार द्वारा खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के लिए नीतियों को लचीला बनाए जाने से कई अंतर्राष्ट्रीय खुदरा कंपनियाँ भारतीय बाजार में आईं।

कालखंड के अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्रवृत्तियाँ

- 1991-2000: यह अवधि आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी, जब सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश को अनुमति दी। शुरुआती वर्षों में निवेश दर धीमी रही, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ा।
 - 2001-2010: इस दशक में भारत में विदेशी निवेश में तेजी आई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत को अपनी विनिर्माण और आईटी सेवाओं का केंद्र बनाना शुरू किया। सेवा क्षेत्र, दूरसंचार और ऑटोमोबाइल उद्योग में निवेश बढ़ा। सरकार ने एफडीआई नीतियों में सुधार किए, जिससे निवेशकों को अधिक स्वतंत्रता मिली।
 - 2011-2021: यह दशक डिजिटल क्रांति और स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास का गवाह बना। भारत सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और 'स्टार्टअप इंडिया' जैसी योजनाएँ शुरू करने से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह को बढ़ावा मिला। खुदरा व्यापार, ई-कॉमर्स और वित्तीय तकनीक (फिनटेक) जैसे क्षेत्रों में निवेश में तेजी आई। COVID-19 महामारी के बावजूद, स्वास्थ्य और डिजिटल क्षेत्रों में विदेशी निवेश बढ़ता रहा।
- सरकार की नीतियाँ और सुधार

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारों ने समय-समय पर नीतिगत सुधार किए हैं। 1991 के उदारीकरण से लेकर हालिया योजनाओं तक, सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

उदारीकरण और नई आर्थिक नीति (1991)

1991 में आर्थिक संकट के दौरान भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति लागू की, जिसके तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) की नीति को अपनाया गया। सरकार ने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई सुधार किए, जिनमें शामिल थे:

- लाइसेंस राज की समाप्ति और विभिन्न उद्योगों में निजी कंपनियों को प्रवेश की अनुमति।
- स्वचालित मार्ग से कई क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति, जिससे निवेश प्रक्रिया सरल हुई।
- विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (FEMA) 1999 के तहत विदेशी निवेश के नियमों को उदार बनाया गया।
- इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन।

इन सुधारों के कारण भारत में विदेशी निवेशकों की रुचि बढ़ी और 1991 के बाद से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह में निरंतर वृद्धि हुई।

विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सुधार

1991 के बाद से, विभिन्न सरकारों ने भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए नए सुधार लागू किए:

- 1999-2004 (वाजपेयी सरकार): दूरसंचार, बीमा, और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में निवेश सीमा बढ़ाई गई।
- 2004-2014 (मनमोहन सिंह सरकार): खुदरा व्यापार, रक्षा, और विमानन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को मंजूरी दी गई।
- 2014-वर्तमान (मोदी सरकार): कई क्षेत्रों में निवेश की सीमा बढ़ाकर 100% तक कर दी गई, जिससे निवेशकों का विश्वास मजबूत हुआ।

‘मेक इन इंडिया,’ ‘स्टार्टअप इंडिया,’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनाओं का प्रभाव

1. मेक इन इंडिया (2014):

भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई। जिसमें ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा मिला। 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कोल, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, और कंस्ट्रक्शन क्षेत्रों में अनुमति दी गई।

2. स्टार्टअप इंडिया (2016):

स्टार्टअप को वित्तीय सहायता और टैक्स लाभ दिए गए। विदेशी निवेशकों को भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया।

3. आत्मनिर्भर भारत (2020):

आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। रक्षा और एग्रीकल्चर सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीतियों में सुधार किए गए।

• आर्थिक विकास पर प्रभाव

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह में निरंतर वृद्धि हुई, जिससे देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि को बल मिला। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, 2000-2023 के बीच भारत ने लगभग 950 बिलियन डॉलर का कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित किया। विशेष रूप से 2021-22 में, भारत ने 84.8 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह देखा, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में सहायक रहा।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से रोजगार सृजन में भी बढ़ोतरी हुई है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश के कारण आईटी, ऑटोमोबाइल, विनिर्माण, और खुदरा क्षेत्रों में लाखों नौकरियाँ पैदा हुईं। उदाहरण के लिए, आईटी क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह से 2022 तक लगभग 50 लाख प्रत्यक्ष और 1.4 करोड़ अप्रत्यक्ष नौकरियाँ सृजित हुईं। इसी प्रकार, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बढ़ते विदेशी निवेश ने देश को एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाया, जिससे उत्पादन बढ़ा और नई नौकरियाँ पैदा हुईं।

तकनीकी उन्नति के संदर्भ में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ने स्वतः चलित मशीनें, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन तकनीकों को भारत में लाने में मदद की। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में जापान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी की कंपनियों के निवेश से अत्याधुनिक तकनीकों का प्रसार हुआ।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का विभिन्न उद्योगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सेवा क्षेत्र, जो भारत की GDP का लगभग 53% योगदान करता है, ने सबसे अधिक विदेशी निवेश आकर्षित किया है। आईटी और वित्तीय सेवाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ने डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया पहल को गति दी। खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश ने ई-कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेज़न और वॉलमार्ट (फ्लिपकार्ट) के लिए भारतीय बाजार में विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। इन प्रभावों के कारण भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख निवेश गंतव्य बन गया है।

• विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में क्षेत्रीय असमानता

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह क्षेत्रीय रूप से असमान रहा है। कुछ गिने-चुने राज्य अधिकांश विदेशी निवेश आकर्षित करते हैं, जबकि कई अन्य राज्यों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह सीमित है। औद्योगिक बुनियादी ढाँचे, व्यापार अनुकूल नीतियाँ और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, और गुजरात जैसे अग्रणी राज्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में आगे हैं।

महाराष्ट्र भारत में सबसे अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने वाला राज्य है। मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे प्रमुख आर्थिक केंद्रों में आईटी, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएँ और विनिर्माण क्षेत्र में बड़े विदेशी निवेश हुए हैं। 2021-22 में महाराष्ट्र को भारत के कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का लगभग 27% प्राप्त हुआ।

कर्नाटक विशेष रूप से आईटी और स्टार्टअप हब के रूप में उभरा है। बेंगलुरु, जिसे "भारत की सिलिकॉन वैली" कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न और अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों का केंद्र बन चुका है। कर्नाटक में तकनीकी बुनियादी ढाँचा और अनुकूल नीति निवेश को आकर्षित करती हैं।

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में मुख्य रूप से सेवा, ई-कॉमर्स, और वित्तीय निवेश को बढ़ावा मिला है। गुडगाँव और नोएडा जैसे क्षेत्र आईटी कंपनियों और स्टार्टअप के लिए केंद्र बने हैं।

गुजरात में व्यापार अनुकूल नीतियों और औद्योगिक गलियारों (DMIC) के कारण पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल, और बंदरगाह आधारित उद्योगों में बड़े निवेश हुए हैं।

इसके विपरीत, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह सीमित है। इसके प्रमुख कारण हैं बुनियादी ढाँचे की कमी, निवेश नीतियों की जटिलता, राजनीतिक अस्थिरता और प्रशिक्षित श्रमिकों की अनुपलब्धता। सरकार "पूर्वोदय" और "मेक इन इंडिया" जैसी नीतियों के माध्यम से इन राज्यों में निवेश बढ़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी सुधार की आवश्यकता है।

• विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के समक्ष चुनौतियाँ

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाह में कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जो निवेशकों के लिए बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। नीतिगत अस्थिरता और नौकरशाही बाधाएँ सबसे बड़ी समस्याओं में से एक हैं। विभिन्न सरकारों द्वारा समय-समय पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीतियों में बदलाव किया जाता है, जिससे विदेशी निवेशकों में अनिश्चितता बनी रहती है। इसके अलावा, लाइसेंसिंग प्रक्रियाएँ, मंजूरी में देरी, और लालफीताशाही निवेशकों को हतोत्साहित करती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में व्यापार सुगमता सूचकांक (Ease of Doing Business Index) में 2014 से सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई मंजूरी प्रक्रियाएँ लंबी हैं।

भूमि अधिग्रहण और श्रम सुधार की समस्याएँ भी निवेशकों के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि अधिग्रहण में कानूनी विवाद और विरोध के कारण देरी होती है। इसके अलावा, श्रम कानूनों की जटिलता के कारण कई कंपनियाँ भारत में विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने से बचती हैं। हालाँकि सरकार ने नए श्रम संहिताओं (Labour Codes) को लागू करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी प्रभावी कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ हैं।

घरेलू उद्योगों पर प्रभाव और विरोध भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राह में बाधा बनता है। विदेशी कंपनियों के आगमन से स्थानीय उद्योगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिससे छोटे और मध्यम उद्यम (MSME) प्रभावित होते हैं। खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को लेकर छोटे व्यापारियों का विरोध देखा गया है, क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होते हैं।

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक कारक भी भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह को प्रभावित करते हैं। COVID-19 महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध, और अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध जैसे कारकों ने वैश्विक निवेश को अस्थिर कर दिया है। भारत-चीन सीमा विवाद के कारण चीन से आने वाले निवेश पर कई प्रतिबंध लगाए गए, जिससे कुछ क्षेत्रों में निवेश प्रभावित हुआ। इन चुनौतियों के बावजूद, सरकार निरंतर सुधार कर रही है ताकि भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाया जा सके।

• भविष्य की संभावनाएँ और सुझाव

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की संभावनाएँ अत्यधिक उज्वल हैं, विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार, विनिर्माण, और हरित ऊर्जा क्षेत्रों में। वर्ष 2022-23 में भारत ने 71 बिलियन डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह दर्ज किया, और अगले पांच वर्षों में इसके और बढ़ने की संभावना है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम

भारत को नीतिगत पारदर्शिता, व्यापार सुगमता, और अवसंरचना विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सरकार को कर सुधारों, स्वचालित अनुमोदन प्रक्रियाओं और श्रम कानूनों को सरल बनाने पर अधिक जोर देना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में 'एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली' (Single Window Clearance) को और प्रभावी बनाना आवश्यक है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की संभावनाएँ

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की संभावना है, जिससे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अपार अवसर खुलेंगे। ई-कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), और 5G तकनीक में निवेश की बड़ी संभावनाएँ हैं। स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएँ विदेशी निवेश को आकर्षित कर रही हैं, जिससे भारत वैश्विक इनोवेशन हब बन सकता है।

नीतिगत सुधार और वैश्विक व्यापार समझौतों का महत्व

भारत को मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) में अधिक भागीदारी करनी होगी, जिससे निवेशकों को स्थिर बाजार मिल सके। भारत-यू.ई. और भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते पहले से ही व्यापार और निवेश प्रवाह बढ़ा रहे हैं। यदि भारत डब्ल्यूटीओ, जी20, और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में अपनी स्थिति मजबूत करता है, तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह को और गति मिलेगी।

• निष्कर्ष

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ने 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद से आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह अध्ययन दर्शाता है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह में सतत वृद्धि हुई है, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), विनिर्माण, खुदरा व्यापार, और सेवा क्षेत्रों में। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों ने अधिक विदेशी निवेश आकर्षित किया, जबकि पूर्वोत्तर और कुछ उत्तरी राज्यों में इसका स्तर अपेक्षाकृत कम रहा। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ने GDP वृद्धि, रोजगार सृजन, और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित किया है। विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप, और ई-कॉमर्स क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाएँ मौजूद हैं। सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया,' 'स्टार्टअप इंडिया,' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी नीतियाँ विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सहायक रही हैं, जिससे औद्योगिक उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा मिला है। हालाँकि, नीतिगत अस्थिरता, नौकरशाही बाधाएँ, भूमि अधिग्रहण की जटिलताएँ और श्रम सुधारों की कमी जैसी चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं। व्यापार सुगमता में सुधार, वैश्विक व्यापार समझौतों में भागीदारी, और पिछड़े राज्यों में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करके भारत अगले दशक में वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश गंतव्यों में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकता है।

संदर्भ

1. गुप्ता, एस. (2005), "भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश : एक आर्थिक विश्लेषण," भारतीय आर्थिक समीक्षा, नई दिल्ली
2. शर्मा, आर. (2010), "वैश्वीकरण और भारत में विदेशी निवेश," इंटरनेशनल बिजनेस जर्नल, मुंबई।
3. सक्सेना, पी. (2013), "विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और भारतीय औद्योगिक विकास," राष्ट्रीय आर्थिक पत्रिका, दिल्ली।

4. मिश्रा, के. (2015), “भारत में विदेशी निवेश की नीतियाँ और उनकी प्रभावशीलता,” आर्थिक नीति विश्लेषण, पटना।
5. चटर्जी, बी. (2018), “सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और भारत की आर्थिक वृद्धि,” भारतीय वित्तीय अध्ययन, कोलकाता।
6. वर्मा, एस. (2012), “भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्रवृत्तियाँ,” दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
7. पटेल, आर. (2014), “विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और भारतीय अर्थव्यवस्था: एक तुलनात्मक अध्ययन,” मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई।
8. त्रिपाठी, एम. (2016), “भारत में विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास,” बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
9. मेनन, के. (2018), “भारत में सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रभाव,” मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई।
10. श्रीवास्तव, पी. (2019), “विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और श्रम बाजार में परिवर्तन,” लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
11. सिंह, वी. (2018), “विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और क्षेत्रीय असमानता,” भारतीय व्यापार एवं वाणिज्य जर्नल, भोपाल।
12. चौधरी, पी. (2021), “भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कानूनी ढांचा,” राष्ट्रीय विधि पत्रिका, हैदराबाद।
13. कर्ण, पी. (2021), “भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और वैश्विक व्यापार समझौते,” अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त समीक्षा, चेन्नई।
14. शुक्ला, आर. (2022), “भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सुधार और आत्मनिर्भर भारत,” राष्ट्रीय नीति अध्ययन, दिल्ली।
15. “भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह में वृद्धि,” (2019), द हिंदू, नई दिल्ली।
16. “खुदरा व्यापार और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश: नए अवसर,” (2020), इकोनॉमिक टाइम्स, मुंबई।
17. “विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सुधार और भारतीय अर्थव्यवस्था,” (2021), बिजनेस स्टैंडर्ड, कोलकाता।
18. “भारत में विदेशी निवेश नीतियों में बदलाव,” (2022), फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दिल्ली।
19. “विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और डिजिटल इंडिया,” (2023), द इंडियन एक्सप्रेस, चेन्नई।